अनुसूचित जातियों की शिक्षा : एक अनुशीलन

अरूण कुमार मिश्रा

अनुसूचित जातियों की शिक्षा में भागीदारी का प्रश्न सचमुच आज का सबसे ज्वलंत और गंभीर विषय है। यह लोकतंत्र में भी भागीदारी का प्रश्न है। यह सर्वविदित ही है कि हिन्दू समाज की वर्णव्यवस्था में शूद्रों को पढ़ने–लिखने का अधिकार नहीं था। इस बात का श्रेय तो ब्रिटिश सरकार को ही जाता है कि उसने अनुसूचित जातियों को पढ़ने–लिखने का अधिकार दिया। ब्रिटिश सरकार ने इनके लिए शिक्षा का द्वार खोलकर इस व्यवस्था को तोड़ा। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ज्योतिराव फुले तथा बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में डॉ. अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति की शिक्षा पर ध्यान दिया और उनकी मुक्ति के लिए सामाजिक आन्दोलन चलाया। 1960 में श्री यू.एन. ढेबर की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित हुआ।